



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 7 मार्च, 2005/16 फाल्गुन, 1926

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 7 मार्च, 2005

संख्या वि० स०-विधायन-गवर्नमेंट बिल/1-18/2005.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2005

(2005 का विधेयक संख्यांक 3) जो आज दिनांक 7 मार्च, 2005 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

जे० आर० गाजड़ा,
सचिव।

हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2005

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त अधिनियम, 1983 (1983 का 17) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2005 है। संक्षिप्त नाम।
 - 1983 का 17 2. हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त अधिनियम, 1983 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 5 की उप-धारा (2) में, शब्दों "किन्तु ऐसी रिक्ति के होने की तारीख से छः मास व्यतीत होने के पहले ही" का लोप किया जाएगा। धारा 5 का संशोधन।
 3. मूल अधिनियम की धारा 15-क में, उप-धारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उप-धारा अन्तःस्थापित की जाएगी :— धारा 15-क का संशोधन।
- “(6) राज्यपाल, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन निर्दिष्ट लोक आयुक्त की शक्तियों और कृत्यों को अध्यक्ष, राज्य मानवाधिकार आयोग को सौंप सकेंगे।”।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री ओ० पी० वर्मा, तत्कालीन लोक आयुक्त, की पंजाब के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति होने से लोक आयुक्त, हिमाचल प्रदेश का पद पिछले एक वर्ष से अधिक समय से रिक्त पड़ा है। हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त अधिनियम, 1983 (1983 का 17) की धारा 5 (2) लोक आयुक्त के कार्यालय में होने वाली रिक्ति को ऐसी रिक्ति होने की तारीख से छः मास की अवधि के भीतर भरने का उपबन्ध करती है। परन्तु उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध न होने से पद भरा नहीं गया। अब लोक आयुक्त की शक्तियों और कृत्यों की अध्यक्ष, राज्य मानवाधिकार आयोग को, जो कि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश भी हैं, सौंपने और उक्त अधिनियम की धारा 5(2) में पद को भरने के लिए नियत समय सीमा का लोप करने का भी विनिश्चय किया गया है। इसके अतिरिक्त यह भी सुविचारित किया गया है कि इन दो संस्थानों में अलग-अलग अध्यक्षों (प्रमुखों) का कोई औचित्य नहीं है। अतः उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उक्त अधिनियम में उपयुक्त रूप से संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है।

यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

वीरभद्र सिंह,
मुख्य मन्त्री।

शिमला :

तारीख : 2005.

वित्तीय ज्ञापन

-शून्य-

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-

हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2005

हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त अधिनियम, 1983 (1983 का 17) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

वीरभद्र सिंह,
मुख्य मन्त्री ।

सुरेन्द्र सिंह ठाकुर,
सचिव (विधि) ।

शिमला :

तारीख 2005.

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 3 of 2005

THE HIMACHAL PRADESH LOKAYUKTA (AMENDMENT)
BILL, 2005

(As INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Lokayukta Act, 1983 (Act No. 17 of 1983).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-sixth Year of the Republic of India, as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Lokayukta (Amendment) Act, 2005.

Amendment
of section 5.

2. In section 5 of the Himachal Pradesh Lokayukta Act, 1983 (hereinafter referred to as the "principal Act"), in sub-section (2), the words, "but not later than six months from the date of occurrence of such vacancy" shall be deleted.

17 of 1983

Amendment
of section
15-A.

3. In section 15-A of the principal Act, after sub-section (5), the following sub-section shall be inserted, namely :—

“(6) The Governor, may by notification published in the Official Gazette, entrust on the Chairperson, State Human Rights Commission, the powers and functions of the Lokayukta specified under this Act.”.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The post of the Lokayukta, Himachal Pradesh is lying vacant for the last more than one year as Mr. Justice (Retired) O. P. Verma, the then Lokayukta, was appointed as the Governor of Punjab. Section 5 (2) of the Himachal Pradesh Lokayukta Act, 1983 (Act No. 17 of 1983) provides for filling up of a vacancy occurring in the office of the Lokayukta within a period of six months from the date of occurrence of such vacancy. But due to non-availability of a suitable person the vacancy could not be filled up. Now, it has been decided to entrust the powers and functions of the Lokayukta on the Chairperson, State Human Rights Commission who is also a retired Chief Justice of the High Court and also to omit the time limit fixed for filling up of a vacancy in section 5(2) of the Act *ibid*. Further, it has also been considered that there is no justification for separate heads of these two Institutions. Thus, in order to achieve the aforesaid objective, it has been decided to amend the Act *ibid* suitably.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

SHIMLA :

The, 2005.

FINANCIAL MEMORANDUM

-NIL-

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-NIL-

THE HIMACHAL PRADESH LOKAYUKTA (AMENDMENT) BILL, 2005

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Lokayukta Act, 1983 (Act No. 17 of 1983).

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

SURINDER SINGH THAKUR,
Secretary (Law).

SHIMLA :

The....., 2005.